मौजूदा मार्केटिंग ईयर में नहीं शुरू हो सका शुगर एक्सपोर्ट

शुगर मिलों में मिनिमम स्टॉक रखने के नए सरकारी नियम को व्यापारी बता रहे हैं वजह

[माधवी सैली | नई दिल्ली]

इस मार्केटिंग ईयर में चीनी का एक्सपोर्ट अब तक शुरू नहीं हो सका है। यह स्थिति तब है जब सरकार की तरफ गन्ना उद्योग को बढ़ावा देने और गन्ना किसानों के लिए 1,540 करोड़ के वित्तीय सहायता पैकेज का ऐलान हो चुका है। इसके तहत किसानों को मिलों में गन्ना सप्लाई करने पर प्रति क्विंटल 5.50 रुपये की अतिरिक्त रकम मिलेगी। 2017-18 में 17.5 करोड़ टन चीनी का निर्यात हुआ था जबकि इस साल अप्रैल से मई के बीच यह 2,40,093 टन रहा है। पिछले साल मार्च में सरकार ने 2017-18 मार्केटिंग ईयर के लिए 20 लाख टन चीनी का निर्यात करने की इजाजत दी थी। इसका मकसद चीनी का सरप्लस स्टॉक खत्म करना और गन्ना किसानों को 20,000 करोड़ का बकाया भुगतान करने के लिए गन्ना मिलों के कैश फ्लो को सुधारा जा सके।

व्यापारियों और निर्यातकों का कहना है कि इस साल अब तक एक्सपोर्ट शुरू नहीं होने की वजह सरकार की तरफ से फरवरी में लागू किया गया योग्यता का नया मापदंड है जिसके तहत मिलों के पास लिमिट के हिसाब से स्टॉक होना चाहिए। इस मापदंड पर 40 पर्सेंट से ज्यादा मिल्स खरा नहीं उतर रहे हैं और वे उलझन में हैं कि उन्हें निर्यात करना चाहिए या नहीं। व्यापारियों ने यह भी कहा कि अगर भारतीय चीनी निर्यातक बाजार में चल रहे 320 डॉलर प्रति टन के भाव के बजाय 280 से 290 डॉलर प्रति टन का दाम लगाते हैं तो अफ्रीका, खाड़ी देशों और दक्षिण एशियाई मार्केट्स के व्यापारियों से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं।

चीनी निर्यातकों ने यह भी कहा कि सरकार 50 से 60 लाख टन सरप्लस चीनी को बफर स्टॉक में बदल सकती है और एक्सपोर्ट के लिए स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, एमएमटीसी लिमिटेड और पीईसी के जरिए टेंडर जारी कर सकती है। इंडियन शुगर मिल्स एसोशिएसन के डायरेक्टर जनरल अविनाश वर्मा ने कहा, '9 मई को जारी सरकारी नोटिफिकेशन के पैरा 2 (सी) की शर्तों में एक रेट्रोस्पेक्टिव एप्लिकेशन भी है, जो खासतौर पर 2017-18 सीजन के 9 मई की तारीख से पहले जारी आदेशों के लिए है। फरवरी-मार्च 2018 तक मिनिमम स्टॉक को बरकरार रखने का मापदंड अभी पूरा नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी समय सीमा पहले ही बीत चुकी है।' वर्मा ने कहा कि हमने फूड मिनिस्ट्री से इस पर स्पष्टीकरण जारी करने का अनुरोध किया है। मुंबई के एक शुगर एनालिस्ट ने कहा कि मिलों को 15 दिनों तक अप्रत्यक्ष तरीके से सब्सिडी देने के बाद भी कुछ खास व्यापार नहीं हुआ है। एनालिस्ट ने कहा, 'समस्या यह है कि मिल पूरी सब्सिडी आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। मिलों की तरफ से ऑफर एफओबी करीब 320 से 330 डॉलर प्रति क्विंटल है जबकि पूरी सब्सिडी आगे तक पहुंचाने पर एफओबी 290 डॉलर प्रति टन होनी चाहिए। ग्लोबल मार्केट में मांग बढ़ाने के लिए भारतीय चीनी का दाम घटाना होगा।' इस साल देश में 3.19 करोड़ टन चीनी का उत्पादन होने का अनुमान है जो पिछले साल 2.03 करोड़ टन रहा था।